

प्रश्नक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लौ0नि0वि0 देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 11 सितम्बर, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में निर्माणाधीन पूल्ड आवास भवन कार्यों हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2777/13 बजट(पूल्ड आवास भवन-वालू कार्य)/ 2007-08 दिनांक 12.07.2007 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0-1761/111-2/07-16(बजट)/2007 दिनांक 06 अगस्त, 2007 के क्रम में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन पूल्ड आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में कुल प्राविधानित धनराशि रु0 300.00 लाख में से रु0 93.30 लाख (रु0 तिरानवे लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि को कम करते हुए अवशेष धनराशि रु0 206.70 लाख (रु0 दो करोड़ छः लाख सत्तर हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आन्तर पर कोषान्तर से आहरण किया जायेगा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वालू /निर्माणाधीन योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्व अनुमति के बिना नई योजनाओं पर व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय वालू कार्यों पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय/भौतिक तथ्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आवास के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करके संबंधित को हस्तगत कर दिये जायेंगे।

7- यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए इसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुदान सं0-22लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परियोजना-80-सामान्य-आवोजनागत-800-अन्वय-12-पूल्ड आवास योजना (वालू कार्य)-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

प्रदीप सिंह रावत

10- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- यू.ओ. 349/XXVII (2)/07, दिनांक 05 सितम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-2176 (1)/111(2)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, भाजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 लोनिवि, पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।